EDU Journal of International Affairs and Research (EJIAR), ISSN: 2583-9993
Volume 3, Issue 4, October-December, 2024, Available at: https://edupublications.com/index.php/ejiar

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

डॉ. राम गोपाल डिडेल[1], सुनिता[2]

[1]राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
[2]MA, NET, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

सारांश :

भारत में न केवल राष्ट्रीय स्तर की पार्टीया ह। बल्कि क्षेत्रीय दल भी है। क्षेत्रीय पार्टी का तात्पर्य उस पार्टी से है जिसका क्षेत्र संचालन सीमित है और इसलिए उनकी गतिविधियां केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित है। दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को संदर्भित करती है जो एक पंजीकृत पार्टी है जो देश के चार से अधिक राज्यों में काम करती हैऔर उनके संचालन का क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है।

राजनीतिक दल देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, क्योंकि वे विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक आवश्यकताओं और राष्ट्र के उद्देश्यों के दृष्टिकोण के होते है। व नागरिकों ओर सरकार के बीच खाई को पाटते है। एक राजनीतिक दल को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एक क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। क्षेत्रीय पार्टी एक राजनीतिक पार्टी को संदर्भित करती है, जिसका एक विशेष क्षेत्र में अपना आधार है और इसके सीमित उद्देश्य है। क्षेत्रीय पार्टी के प्रतीक को दूसरे राज्य में बदला या दोहराया जा सकता है। क्षेत्रीय पार्टी का असर कम से कम एक या दो राज्यों में होता है। क्षेत्रीय पार्टी का लक्ष्य क्षेत्रीय हित को बढावा देने के लिए होता है।

क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पंजीकृत पार्टी द्वारा निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जाना है :–

1. यदि पंजीकृत पार्टी संबंधित राज्य के विधान सभा के चुनाव के दौरान राज्यों में डाले गए वैध मतो का 6 प्रतिशत पर कब्जा कर लेती है और वह राज्य विधानसभा में 2 सीटे प्राप्त कर लेती है।
2. यदि पंजीकृत पार्टी संबंधित राज्यो से संसद के निचले सदन यानि लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में डाले गए वेद्य मतो का 6 प्रतिशत सुरक्षित करती है और यह संबंधित राज्य की लोकसभा में एक सीट प्राप्त करती है।
3. यदि पार्टी राज्य विधानसभा की 3 प्रतिशत सीटों पर आम चुनावों में संबंधित राज्य की विधानसभा में या तीन विधानसभाओं में, जो भी अधिक हो, का अधिग्रहण करती है।
4. यदि पंजीकृत पार्टी संसद के निचले सदन में प्रत्येक 25 सीटो या संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को सौपे गए किसी भी हिस्से के लिए एक सीट का अधिग्रहण करती है।
5. यदि पंजीकृत पार्टी राज्य के आम चुनावों में राज्य से या राज्य विधानसभा के निचले सदन में डाले गए कुल वैध मतों का 8 प्रतिशत प्राप्त करती है।

संकेताक्षर :–
राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय दल, चुनाव, राष्ट्रीय, मतदान, क्षेत्रीय पार्टियां

भारतीय राजनीति के लिए कितने महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय दल

भारत में समय–समय पर अलग–अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता रहा है और ये देश के संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती रही है। शिरोमणि अकाली दल और जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस जेसे कुछ पार्टियां तो 1947 में देश के आजाद होने से भी पहले गठित हो गई थी। लेकिन ज्यादातर दसरी क्षेत्रीय पार्टियां देश के आजाद होने के बाद ही गठित हुई है।

क्षेत्रीय दलों की श्रणी में रखी जाने वाली पार्टियों का विकास खास तौर पर 1967 के बाद तेज हुआ, जब देश के स्वतंत्रता संग्राम में खास भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की देश के मतदाताओं पर पकड़ ढीली होने लगी।

इस समय लगभग चार दर्जन राज्य स्तरीय पार्टियों को चुनाव आयोग की मान्यता हासिल है और लगभग दो दर्जन ऐसी है जिन्हें अब तक मान्यता नहीं मिली है। इनमें से कई अपने राज्य में सत्ता में है तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियों ने लोकप्रियता हासिल कर राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती पेश कर दी है। इन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से क्षेत्र या राज्य विशेष की राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा को अपना आधार बनाया और आगे बढ़ी।

सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में धार्मिक संगठन शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने की ताकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अविभाजित पंजाब में सिखो की मुख्य प्रतिनिधि बन सके।

इस समय क्षेत्रीय पार्टियां आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू–कश्मीर, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने अकेले दम पर राष्ट्रीय पार्टी अथवा किसी और पार्टी के साथ मिल कर शासन कर रही है।

इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों की एक खासियत यह है कि ये सभी एक ऐसे नेता के इशारे पर चलती है जिसकी सत्ता को पार्टी के अंदर कोई चुनौती नहीं दे सकता। संक्षेप में कहें तो इन्हें कोई एक नेता और उसके विश्वासपात्र चला रहे है। उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों का भी पार्टी के काम–काज में खासा दखल रहता है।

जो पार्टियां किसी वैचारिक आधार पर गठित हुई है, उन्हें भी समय के साथ व्यक्तिगत जागीर और व्यक्तिगत हितों की रक्षा का साधन बना दिया गया है। इसलिए सामान्य तौर पर ऐसी पार्टियों का अस्तित्व भी उनका संचालन करने वाले नेता के जीवन काल से काफी नजदीक से जुड़ा है।

क्षेत्रीय संगठनों की एक और खास बात यह है कि परिवार के सदस्य नजदीकी रिश्तेदार और मित्र पार्टी के काम का संचालन करते है और उनमें से ही एक उसके नेता की विरासत को उसके जीवन काल के दौरान या उसके बाद संभाल लेता है।

हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी (सपा) के सबसे ताकतवर नेता और उनके बेटे के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के खुल कर सामने आ जाने की वजह से यह पार्टी चर्चा में है। इसलिए क्षेत्रीय दलों की विडंबना और इनके भविष्य को समझने के लिए सपा को नजदीक से समझना दिलचस्प होगा।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदश पर सपा का 2012 से 2017 तक में शासन था और 1992 में इसके गठन के बाद से यह लगभग एक दशक तक सत्ता में रही है। इसने केंद्र में भी सत्ता में साझेदारी की है।
पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग हो कर किया था। 1990 के दशक की शुरूआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद मुलायम का प्रभाव काफी बढ़ा। इससे पहचान की राजनीति को भी खास कर उत्तर भारत में काफी बढ़ावा मिला था।

मुलायम 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस पद पर पूरे एक साल और 201 दिन तक रहे। 1991 के आम चुनाव में जनता दल की हार के बाद उन्हें यह कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सपा की स्थापना की ओर दो बार मुख्यमंत्री बने।

इस साल 22 नवंबर 2022 को वे 83 वर्ष के हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि अब वे उतने स्वस्थ नहीं रहते। पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से वर्चस्व की लड़ाई कभी खुल कर, तो कभी दबे–छुपे चल ही रही है

लेकिन जितना खुल कर यह अब सामने आई है, इतनी कभी नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव क गुट मुलायम सिंह के बाद के युग के लिए खुद को तैयार कर रहे है। अखिलेश जहां मुलायम के सबसे बड़े बेटे है, वहीं शिवपाल उनके छोटे भाई है।

पार्टी में खुद अपनी सत्ता को चुनौती मिलती देख कर और पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह ने दखल दिया और एक ऐसा रास्ता दिया जो उनकी नजर में राजनीतिक रूप से उनको प्रासंगिक भी बनाए रखता और अगले चुनाव में सत्ता बनाए रखने की पार्टी की उम्मीद को भी जिंदा रखता।

मुलायम की ओर से पेश किए गए एकजुटता के प्रदर्शन को अखिलेश और सपा के नव नियुक्त प्रदश अध्यक्ष शिवपाल ने जारी रखने से इंकार कर दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 25 साल पुरानी पार्टी पार्टी के सामने इसके अस्तित्व को ले कर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। इसमें बहुत सी दरारें आ गई है, जिनका मुलायम ढंक रहे है।

यह समझते हुए कि उनके बेटे के कदम अगले चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना को काफी नुकसान पहुंचा सकते है, मुलायम ने दखल दिया और शिवपाल का गुस्सा ठंडा करने के लिए अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर उन्हें इस पर बिठा दिया। मुख्यमंत्री के लिए यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश माने नहीं और उन्होंने भी शिवपाल और अपने पिता के पसंदीदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

शिवपाल को न सिर्फ राज्य में पार्टी का प्रमुख बना दिया गया, बल्कि मुलायम ने यह भी सुनिश्चित किया कि अखिलेश की ओर से उठाए गए सभो कदम वापस ले लिए जाएं। सपा के शीर्ष पुरूष एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बना दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने 'बाहरी' व्यक्ति बताया था।

पार्टी से 2010 में निष्कासित कर दिए गए अमर सिंह को वर्ष 2016 मई मे दुबारा पार्टी में शामिल किया गया था और पार्टी की ओर से राज्य सभा भी भेज दिया गया।

इसी तरह पार्टी के नेता रामगोपाल यादव है, जो पार्टी सुप्रीमों के चचेरे भाई होने के साथ ही पार्टी के ऐसे विचारक भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर अहम मुद्द पर मुलायम उनसे जरूर संपर्क करते है। दूसरी तरफ मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और उनके महत्वाकांक्षी बेटे प्रतीक यादव है, जो बड़े स्तर पर जमीन–जायदाद का कारोबार करते है। यादव परिवार की आतंरिक लड़ाई में इन सभी के हित दांव पर लगे है।

जिम्मेवारी संभालने के तुरंत बाद शिवपाल ने ततपरता दिखाते हुए अखिलेश से करीबी रखने वाले सात युवा नेताओं को निकाल दिया। इससे पहले उन्होंने एक विधान पार्षद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी जो मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के नजदीकी रिश्तेदार है।

2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसान, युवाओं व महिलाओं पर फोकस करते हुए समाज के सभी वर्गो को लुभाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों पर अभी 2022 के चुनाव में 255 सीटे बीजेपी ने और 111 सीटे सपा ने जीती। जो पिछले चुनाव ने बीजेपी की 312 सीटे ओर सपा ने 47 सीटे जीती थी।

सपा जिन चुनौतियों का समाना कर रही है वह कोई अपवाद नहीं है और लगभग यही खतरे उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों के ढांचे में ही निहित है जो या तो सत्ता में है या सत्ता पाने के लिए संघर्षरत है।

बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता में रही और हर बार इसकी एकमात्र सर्व शक्तिमान नेता मायावती मुख्यमंत्री बनी। पार्टी की स्थापना 1984 में काशी राम ने इस उद्देश्य के साथ की

थी कि बहुजन समाज यानी दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) और अल्पसंख्यको को सत्ता में पतिनिधित्व मिल सकें।

स्वर्गीय कांशी राम ने पूर्व स्कूल अध्यापिका मायावती को अपना उतराधिकारी बनाया। उनकी मौत के बाद बसपा का वजूद पूरी तरह मायावती के उपर ही टिक गयो। उनके नेतृत्व को पार्टी में किसी और नेता की ओर से न तो चुनौती दी जा सकती है न ही कोई सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के बहुत से दलित उन्हें अपना नेता मानते है।

हालांकि पार्टी ने अपने सिद्धांतों की प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार ईवी रामासामी और छत्रपति शाहूजी महाराज से हासिल की है, लेकिन 1990 के दशक की शुरूआत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद मायावती ने अपना लक्ष्य और दर्शन किसी भी तरह सत्ता हासिल करना बना लिया है। वर्षो से अब बसपा को एकजुट रखने वाली ताकत वही है। इसलिए अब तो उनके बिना बसपा की कल्पना भी करना नामुमकिन लगता है। जब तक कि वे अपने उतराधिकारी को तैयार करना शुरू नहीं कर दे ऐसा लगता है कि उनके सामने नहीं रहने पर पार्टी के तितर–बितर हो जाने में देर नहीं लगेगी। आज के समय में पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनकी अनुपस्थिति में इसे चला सके। सन् 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में बसपा को मात्र 1 (एक) सीट मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बसपा अभी यूपी में राजनीतिक मुख्यधारा में नहीं है।

इसी तरह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की ही एक और पार्टी राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, जिसकी स्थापना पूव केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने 1996 में की थी। राज्य के जाट बहुल जिला मे इसका प्रभाव है। अजीत सिंह को राजनीति की विरासत अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिली, मगर वे सत्ता में बने रहने क लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रोय पार्टियों सहित विभिन्न पार्टियों से गठबंधन करते रहे है ताकि सत्ता में प्रासंगिक बने रहें। अब माना जा रहा है कि उनकी कमान जयंत चौधरी संभालेंगे जो मथुरा से एक बार सांसद भी रहे है। सन् 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटे जीती और सपा के साथ गठबंधन में थी। सन् 2017 में विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल कई बार सत्ता में रही है लेकिन 1970 में जब प्रकाश सिंह बादल चौथे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पार्टी में पूरी सत्ता उनके परिवार के ही पास केंद्रित हो गई है। भाजपा और अकाली का गठबंधन 2007 से सत्ता में थी। प्रकाश सिंह बादल के बेटे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कोर बादल केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थी। सन् 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली।

पड़ोस के राज्य हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलोद) की स्थापना पूर्व उप प्रधान मंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवी लाल ने अक्टूबर 1996 में हरियाणा लोक दल के रूप में की जिसका नाम बदल कर 1998 में इनेलोद कर दिया गया। देवी लाल के बेटे ओमप्रकाश चौटाला पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष है और चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे है। सन् 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 1 (एक) सीट मिली उसका कारण जेजेपी पार्टी है।

तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीमके) की स्थापना पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अन्नादुरै ने 1949 में की और इसने पहला विधानसभा चुनाव 1967 में जीता। तब से डीएमके में बहुत से बदलाव आए है, जिनमें 1972 में हुआ इसका विभाजन भी शामिल है। तब इसके कोषाध्यक्ष और लोकप्रिय फिल्म कलाकार एमजी रामाचंद्रन ने एक नई पार्टी गठित कर ली जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआइएडीएमके)। इसके बाद से राज्य में यही दो पार्टियां बारी–बारी से सत्ता संभाल रही है।

ये पार्टियां काफी हद तक अपने एकमात्र नेता की व्यक्गित जागीर में बदल गई है। डीएमक का नियंत्रण पांच बार मुख्यमंत्रो रहे करूणानिधि के हाथ में 1967 से 2018 में अपनी मौत तक था, जबकि एआईएडीएमके का नियंत्रण पहले एमजी रामाचंद्रन के हाथ में था उसके बाद उनकी सहकर्मी रही जे. जयललिता के हाथ में था। 1987 में एमजी रामाचंद्रन की मृत्यु के बाद से उनकी पार्टी की जिम्मेवारी जयललिता के हाथ में आ गई थी।

वे भी पांच बार मुख्यमंत्री रही है। अभी करूणानिधि का छोटा पुत्र एम के स्टालिन तमिलनाडु राज्य का मुख्यमंत्री है।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दला से अलग नहीं है। यह भी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होने वाली पार्टी है। ममता का आदेश ही आखिरी फैसला होता है जिस पर पार्टी में कोई मशविरा होने का सवाल तक नहीं है।

इस साल की शुरूआत में ममता के प्रभाव की वजह से ही पार्टी राज्य में तीन दशक तक राज करने वालो वामपंथी पार्टियों और भाजपा को पछाड़ कर दुबारा सत्ता में आ सकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 295 में से 215 सीटे जीती है जो पिछले बार 211 सीटे जीत ममता मुख्यमंत्री बनी थी।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी दो क्षेत्रीय दलों तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का शासन है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को ले कर चले आंदोलन से ही 2001 में टीआरएस का जन्म हुआ था।

2014 में हुए राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में यह पार्टी सत्ता में आई ओर इसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव राज्य केपहले मुख्यमंत्री बने। राव पार्टी के अध्यक्ष भी है और राज्य के मुख्यमंत्री भी । उनके पुत्र के.टी. रामाराव राज्य सरकार में मंत्री है और बेटी के कविता निजामाबाद से 2014–2019 तक लोकसभा सांसद भी रह चुकी है, और सन् 2020 से विधान परिषद की सदस्य है।

इसी तरह टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके है। अपने ससुर एन.टी. रामराव के निधन के बाद से उन्होंने ही पार्टी की कमान संभाली है और इस दौरान वे 1995 से 2004 तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वर्ष 2014 से 2019 तक राज्य की कमान संभाल चुके है।

ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) की स्थापना 1997 में हुई और इसके तीन साल बाद यह पार्टी सत्ता में आ गई, जिसके बाद से यह लगातार सत्ता में है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने लगातार पांच विधानसभा चुनाव जीते है पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तब की भाजपा नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार में केंद्रीय खनन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

वर्ष 2000 का यह चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में ही लड़ा था। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजद ने भाजपा से चुनाव गठजोड़ तोड़ लिया। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह यहां भी नवीन पटनायक ही सभी फैसले लेते है। बीजद भी कई मामलों में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से मेल खाती है।

आन्ध्र प्रदेश में वाई एस आर कांग्रेस का बोलबाला 2011 से है इसके वर्तमान अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी है और सन् 2019 से आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जगनमोहन रेड्डी भूतपूर्व आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के पुत्र है।

जहां ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्ति आधारित और एक व्यक्ति या उसके परिवार से संचालित हो रही है, इनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता का हस्तांतरण नए उतराधिकारी को कितनी आसानी से होता है। सत्ता परिवार के जितने ज्यादा सदस्यों के बीच बंटी होगी, पार्टी के बिखरने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मामले में देख रहे है।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय राजनीतिक दल राज्य के विकास को गति देते है और स्थानीय समस्याओं को क्षेत्रीय पार्टियां अच्छी से समझती है बजाय राष्ट्रीय दलों के क्षेत्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता सीधे रूप से उपर तक जुडे होत है इससे विकास में गतिशीलता आती है।

संदर्भ सूची

[1]. डॉ. जनक सिह मीना (सं) भारतीय राजनीति एवं केन्द्र राज्य संबंध, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2015
[2]. डॉ. जनक सिंह मीना, राजस्थान, प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2020
[3]. डॉ. जनक सिंह मीना, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली डॉ. जनक सिह मीना दानालपुर 2020
[4]. शशीकांत मनि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी और भारतीय राजनीति ए.एस.आर. पब्लिकेशन, ISBN - 9788192490250, 8192490254
[5]. रतनेश कुमार मिश्रा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल रावत बुक्स ISBN 10-8131604284 ISB-13-978-8131604281
[6]. www.hindustantimes.com
[7]. www.thehindu.com
[8]. Hasan zoya, parties and party politis in india : Themes in politics, Oxford University Press, Edition 2004 ASIN = 0195668332
[9]. Rajni Kothari, Politics in India, Orient Blackswan (1 Jan 2012) ISBN = 8125042814
[10]. Expert Panel of GPH, भारत में राज्यीय राजनीति, Gullybaba publcation
[11]. Bansal Rajeev, भारतीय शासन एवं राजनीति SBPD Publications, ISBN = 9789351671206, ISBN = 9351671208
[12]. Tiwari R K, Political parties, party Manifestos and Elections in India 1909-2014, Publisher Taylor & Francis 2018, ISBN=9780367184926
[13]. जालान विमल, भारती की राजनीति : संसद के गलियारों से भारतीय राजनीति पर एक नजर Publisher : Penguin ISBN = 9780143063353, 01430663359
[14]. डॉ. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भारतीय राजनीति के समकालीन मुद्दे Hard covers ISBN = 9788178442532, 8178442531
[15]. बाली सूर्यकान्त, भारत की राजनीति का उत्तरायण, प्रभात प्रकाशन संस्करण (1 जनवरी 2019) ISBN = 9353225795, ISBN = 978-9353225797